::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road
राजकोट / Rajkot – 360 001
Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

क अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ **Date:**
V2/13/BVR/2019	**R-57/2018-19**	**11/02/2019**

ख अपीलआदेशसंख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-232-2019

आदेश का दिनांक/ Date of Order:	**25.09.2019**	जारी करने की तारीख / Date of issue:	**04.10.2019**

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by **Shri Gopi Nath**, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot/Jamnagar/Gandhidham :

घ अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the**Appellants**&Respondent :-

M/s.Jai Bharat Steel Industries, 204, GIDC-II, Sihor, Distt: Bhavnagar, Gujarat.

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, ,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :

(C) **Revision application to Government of India:**

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

:: ORDER-IN-APPEAL ::

Shri Pravin Bansal, Partner of M/s. Jai Bharat Steel Industries, 204, GIDC – II, Sihor, Dist - Bhavnagar (hereinafter referred to as 'Appellant') has filed the present appeal against Order-In-Original No. R-57/2018-19 dated 11.02.2019 (hereinafter referred to as 'the impugned order'), passed by the Assistant Commissioner, CGST Division, Bhavnagar - I (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. The facts of the case in brief, are that Show Cause Notice F.No. V/15-117/Dem/HQ/15-16 dated 26.02.2016 was issued to the M/s. Jai Bharat Steel Industries, Sihor and three others including appellant i.e. partner of firm for clandestine clearance of M.S. Ingots to various customers. The above SCN was adjudicated by adjudicating authority vide the order in original No. 04/Excise/Demand/2017-18 dated 26.04.2017 and confirmed demand of Central Excise duty of Rs. 17,50,202/- under Section 11AA of the Act and also imposed penalty of 17,50,202 under Section 11AC(1)(c) of the Central Excise Act, and also impose penalty of Rs. 17,50,000/- upon appellant under the provision of Rule 26(1) of the Central Excise Rules, 2002.

2.1 Being aggrieved M/s. Jai Bharat Steel Industries, Sihor and three others including appellant preferred to appeal before Commissioner (appeal) and pre-deposited Rs. 1,31,270/- vide challan no. 00655 dated 04.07.2017. The Commissioner (Appeal) decided the matter vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-172 to 175-2018-19 dated 12.07.2018 and upheld the above OIO i.e. duty demand and penalty confirmed against M/s. Jai Bharat Steel Industries, Sihor as proposed in said OIO but reduced penalty from Rs. 17,50,000/- to Rs. 5,00,000/- against the appellant under the provision of Rule 26(1) of CER, 2002. The appellant preferred appeal against said OIA before Hon'ble Tribunal and paid Rs. 50,000/- as pre-deposit i.e. 10% of reduced penalty of appellant. The appellant had filed refund claim of Rs. 1,31,270/- paid at the time of appeal filed before Commissioner (Appeal). The adjudicating authority vide OIO No. R-57/2018-19 dated 11.02.2019 rejected the refund claim of appellant.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred the present appeal, *interalia,* on the following grounds:

(i) The impugned order passed by the adjudicating authority is not proper and legal and violated the principle of natural justice and avoided settled case laws. The adjudicating authority had wrongly and without authority confirmed demand and penalty imposed on M/s. Jai Bharat

Steel Industries, Sihor and three others including appellant; Appellate authority vide OIA dated 13.07.2018 reduced penalty from Rs. 17,50,000/- to Rs. 5,00,000/- against the appellant under the provision of Rule 26(1) of CER, 2002. The appellant has filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, Ahmedabad after making mandatory Pre-deposit of Rs. 50,000/- which is 10% of reduced penalty of Rs. 5,00,000/- deposited vide challan no. 00186 dated 05.10.2018 and filed refund claim of Rs. 1,31,270/- which was paid up mandatory pre-deposit as required under Section 35F of the Central Excise Act,1944 at the time of filing the appeal before the Appellate authority. The adjudicating authority has rejected the refund claim of Rs. 1,31,270/- vide their OIO dated 11.02.2019 and violated provision of Section 35F of the CEA,1944.

(ii) The appellant in this regard, relied on following case-laws: -

- 2018 (13) GSTL 144 (Del)- Santani Sales Organization V/s CESTAT, New Delhi.
- 2012 (283) ELT 369 (Ker) – Commissioner of Customs, Cochin V/s. Shree Simandar Enterprises.
- 2014 (304) ELT 281 (Tri.Del) – Balkrishna Industries Ltd. V/s. Commiissioner of Central Excise, Jaipur – I.
- 2012 (283) ELT 353 (Ker) P. P. Suresh V/s. Assistant Commissioner of Customs (Refund) Cochin.

4. Personal hearing in the matter was held and attended by Shri N.K.Maru and Shri U.H.Qureshi, Consultants, Central Excise, Service Tax and Customs, who reiterated Grounds of Appeal and submitted that their appeal may be decided on the basis of above facts and legal position

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and the written as well as oral submission made during the personal hearing. The issue to be decided in the present case is as to whether the appellant is eligible for refund of pre-deposit of Rs. 1,31,270/- at the time of appeal filed before appellant authority against OIO No. 04/Excise/Demand/2017-18 dated 26.04.2017.

6. I find that vide master circular No. 1053/02/2017-CX dated 10.03.2017 Board has clarified about Show Cause Notice, Adjudication, recovery matters and also on refund of pre-deposits. Conditions / procedures for refund of pre-deposits laid down at Sr.No. 26 of above circular, reads as under: -

(i) *Where the appeal is decided in favour of the party / assessee, he shall be entitled to refund of the amount deposited along with the interest at the prescribed rate from the date of making the deposit to the date of refund in terms of 35FF of the Central Excise Act, 1944.*

(ii) *Pre-deposit for filing appeal is not payment of duty. Hence, refund of pre-deposit need not be subjected to the process of refund of duty under Section 11B of the Central Excise Act,1944. Therefore, in all cases where the appellate authority has decided the matter in favour of the appellant, refund with interest should be paid to the appellant within 15 days of the receipt of the letter of the appellant seeking refund, irrespective of whether order of the appellate authority is proposed to be challenged by the Department or not.*

(iii) .....

(iv) .....

(Emphasis supplied)

7. Further, I find that vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-172 to 175-2018-19 dated 12.07.2018, the appellant authority has held at para no. 8.1; that the imposition of penalty upon him as partner under Rule 26(1) of the Rules in addition to imposition of penalty on his partnership firm is correct, legal and proper. However, penalty equal to duty imposed on him, even when penalty equal to duty on partnership firm has been imposed is harsh. I therefore, reduce penalty on Appellant No.2 (present appellant) to Rs. 5 lakhs to meet the interest of justice.

7.1 Further, I find that appellant has not fulfilled conditions laid down at Sr.No. 26(i) of Circular No. 1053/02/2017-CX dated 10.03.2017 as the appellant authority has given relief to appellant on penalty imposed on him under Rule 26(1) and therefore, it is clear that the appeal has not been decided in favour of appellant.

7.2 I also find that the case laws referred by the appellant are not applicable to present case being not related to situation of present case of refund of pre-deposit under Section 35F of the Central Excise Act,1944.

8. In view of the above, I upheld the impugned Order.

९.१ अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9.1. The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

सत्यापित
संजय शेठ
अधीक्षक (अपील)

(Gopi Nath)
Commissioner (Appeals)

<u>By Speed Post</u>

To,
Shri Pravin Bansal,
M/s. Jai Bharat Steel Industries,
204, GIDC – II, Sihor, Dist - Bhavnagar

Copy to:

1. The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, GST & Central Excise, Bhavnagar Commissionerate, Bhavnagar.
3. The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division-, Bhavnagar.
4. Guard File.